







हिंदी दैनिक, जन एक्सप्रेस

@janexpressnews

janexpresslive

www.janexpresslive.com/epaper



किसानों ने शंभू बॉर्डर से दिली मार्च टाला...  
पटियाला। पंजाब के 101 किसान रविवार (४ दिसंबर) को दोपहर 12 बजे पैदल शंभू बॉर्डर से दिली के लिए रवाना हुए, लेकिन पुल पर हीरायाणा पुलिस ने उड़े रोक लिया। करीब पाँचे 4 घंटे बाद जत्थे को वापस लौटना पड़ा। शुरुआत में पुलिस और किसानों के बीच बहस हुई। ► पढ़ें 12 पर...

03

# दूध के उत्पादन में यूपी की बादशाहत बरकरार

## नंद बाबा, गोकुल मिशन, दुग्ध उत्पादन समितियों को प्रोत्साहन व नस्ल सुधार के कार्यक्रम दे रहे शानदार परिणाम



- पशुपालकों के हित में लगातार कदम उठा रही योगी सरकार
- दूध के अलावा सह उत्पादों को भी आर्थिक रूप से उपयोगी बना रही सरकार
- डेयरी क्षेत्र महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रभावी जरिया

जन एक्सप्रेस | लखनऊ

बेसिक एनिमल हानबंडरी स्टैटिस्ट्स 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार देश में दूध का कुल उत्पादन 239.30 मिलियन टन है। इसमें उत्तर प्रदेश का योगदान सर्वाधिक, करीब 16 फीसद का है। इसके बाद क्रम से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्रप्रदेश,

महाराष्ट्र और पंजाब का नंबर आता है। इस तरह दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश की बादशाहत बरकरार है। इसकी एक बड़ी वजह इस सेक्टर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निजी

स्विं और अपने पहले कार्यकाल से ही पशुपालकों के हित में उत्तर प्रदेश की बादशाहत करने के लिए कदम हैं। सरकार प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक पशुपालकों को प्रोत्साहन देने के लिए उनको नंद बाबा

### पीसीडीएफ और दुग्ध संघ सहकारिता से समृद्धि के नारे का साकार करें: सीएम

सहकारिता से समृद्धि सरकार का नारा है। डेयरी सेक्टर में सहकारिता से चमकार का संभव है। दुनिया का सबसे मज़बूत ब्रांड अमूल इयको मिसाल है। इसलिए सरकार इस पर सरकार का खासा फोकस है। हाल ही में मुख्यमंत्री मिसाल हुआ था। इसमें उन्होंने निर्देश दिया था कि दुग्ध संघों में हर स्तर पर जवाबदेही तय करें हुप कार्प के टारेट तथा किये जाएं। दुग्ध संघ क्षमता बढ़ाते हुए दूध की गुणवत्ता के कार्यों को बहता करने करे। सामीत से जुड़े कर्मियों का उचित प्रशिक्षण कराया जाए, उन्हें उपकरण कराये जाएं और समितियों एक दूसरे से स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा करें। पशुपालकों से संबंध बढ़ाएं। सरकार के इन कदमों से डेयरी संघों की दुग्ध उत्पादकता में बढ़ि होनी और किसानों की आय भी बढ़ेगी।

और गोकुल पुरस्कार से सम्मानित करती है। यिथे दिनों नस्ल सुधार के जरिए उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑटोलिया सरकार ने प्रदेश सरकार से सहयोग की इच्छा जताई थी। सरकार नस्ल सुधारने के लिए सेक्स सॉर्टिंग

तकनीक (इसमें सिर्फ बछिया होने की संभावना 90 फॉरेस्ट से अधिक होती है) का प्रयोग कर रही है। गोरखपुर में खुलने वाले राजकीय पशु चिकित्सा महाविद्यालय भी नस्ल सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

### छोटे और भूमिहीन किसानों को होता है पशुपालन से सर्वाधिक लाभ

अधिकांश पशुपालक कम जोत वाले या भूमिहीन किसान हैं। इनके द्वारा पाले जाने वाले दुखालू पशु इनके लिए एटीएम सेरीखे हैं। पशुपालन में हुए किसी भी अच्छे कार्य का बेततर अपर इन पर ही पड़ेगा। यह तकाक योगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपनी पहली कैबिनेट में ही लघु और सीमांत किसानों का एक लाख रुपये तक का ऋण माफ कर वह इसे सावित भी कर चुके हैं। पशुपालन को प्रोत्साहन भी उसकी एक कही है।

### दूध के अलावा सह उत्पादों को भी आर्थिक रूप से उपयोगी बना रही सरकार

योगी सरकार पशुपालकों के अधिकांश हित में दूध के साथ गोबर, गोमूत्र आदि को भी आर्थिक रूप से उपयोगी बना रही है। मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि किंगबर से कम्प्रेस बायो जैस (सीटीजी) प्लाटर स्थापित किये जाएं।

### डेयरी क्षेत्र महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रभावी जरिया

डेयरी सेक्टर महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रभावी जरिया है। सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं की संख्या भी सर्वाधिक है। ऐसे में इस सेक्टर से महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में जड़ने की जरूरत है। कुछ जगहों पर महिलाओं का समूह इस सेक्टर में अनुकरणीय काम भी कर रहा है। बुद्धेलखण्ड क्षेत्र में ललिमा मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी इसका उदाहरण है। अनेक जगहों पर भूमिहीन किसानों की आय भी बढ़ेगी।

### सुधरेंगी जन और जमीन की सेहत

दूध का उत्पादन और प्रति वर्ष की प्रति ग्राम दूध की उपलब्धता बढ़ाने से लोगों की सेहत सुधरेंगी। यह लगातार बढ़ रही है। 2021 में प्रति वर्ष की प्रति ग्राम दूध की उपलब्धता 321 ग्राम थी। 2024 में यह बढ़कर 471 ग्राम हो गई। दूध के उत्पादन की सालाना वृद्धि दर 3.78% है। स्वाभाविक है कि इसमें सर्वाधिक उत्पादन के नाते उत्तर प्रदेश का योगदान भी सर्वाधिक है।

## यूपी में पराली जलाने की घटनाओं में आई कमी 4 हजार से अधिक मामलों में दर्ज की गई गिरावट

योगी सरकार के नेतृत्व में फसल अवशेष प्रबंधन से प्रदूषण में आई भारी कमी, पराली जलाने की घटनाओं में भी दर्ज की गई गिरावट



जन एक्सप्रेस | लखनऊ

योगी सरकार ने कृषि और पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में उत्तराखण्ड राज्य की योगी सरकार के नियमों में नजर डालें तो पराली जलाने के 4,783 मामलों में कमी दर्ज की गयी है। योगी सरकार की नीतियों के जरिये प्रदेश के अंतर्द्वारा पराली को जलाने की जगह उत्तराखण्ड आनी आय बढ़ा में लगातार पराली जलाने की घटनाओं में तेजी से गिरावट हो रही है। प्रदेश में वर्ष 2017 में जहां पराली जलाने के 8,784 मामले दर्ज किये गये थे,

### हर वर्ष लगभग 2.096 करोड़ मीट्रिक टन पराली का हो रहा रहा उत्पादन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के प्रतीक एक दूध की मेल वाली में मुख्य सिविल मोज़ कुमाऊँ सिंह ने पराली प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में बाताया गया कि प्रदेश में हर वर्ष लगभग 2.096 करोड़ मीट्रिक टन पराली का उत्पादन होता है। इसमें से 34.44 लाख मीट्रिक टन वारा व 16.78 लाख मीट्रिक टन पराली की उत्पादन होता है। इसी तरह 1.58 करोड़ मीट्रिक टन पराली इन-सीटू एवं मैनेजमेंट के जरिए उत्पादित किया जा रहा है। यही बजह है कि योगी सरकार द्वारा उत्तराखण्ड में सरकारी उपकरण की विस्तृती द्वारा उत्पादन की घटनाओं में बढ़ी गिरावट आई है। इससे प्रदेश में प्रदूषण में भी कमी आई है। इससे न केवल पर्यावरण की लाभ पूर्ण रहा है बल्कि किसानों को उनके अवशेषों के आंदोगिक और घरेलू उपयोग के माध्यम से आय के नए स्रोत उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

**सरसे कम फतेहपुर में पराली जलाने के 111 मामले आए सामने**  
योगी सरकार द्वारा पराली के आंदोगिक और घरेलू उपयोग करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों में ग्रामीण पराली की उपलब्धता बढ़ावा देकर मिट्टी की उर्वरता में सुधार किया गया। इससे किसानों की घटनाओं में बढ़ि हो रही है। इससे प्रदेश में प्रदूषण में भी कमी आई है। इससे न केवल पर्यावरण की लाभ पूर्ण रहा है बल्कि किसानों की घटनाओं की नियन्त्रित करने में कई जिलों ने अहम भूमिका निभाई है। इनमें से 151, कुशीगढ़र में 111 में दर्ज की गई है। इनमें से सरसे कम घटनाएं महाराजगढ़ में 468, झारी में 151, कुशीगढ़र में 118 और फतेहपुर में 111 में दर्ज की गई हैं। इन जिलों ने बैठक आयोग और जगरनीयों के अंतर्गत पराली को जलाने की समर्यादा जो लाभ समय से आय के नए स्रोत उपलब्ध कराए जा रहे हैं। योगी सरकार की नीतियों के जरिये प्रदेश के अंतर्द्वारा पराली को जलाने की जगह उत्तराखण्ड आनी आय बढ़ा रही है। इससे अब उत्तराखण्ड की घटनाओं में तेजी से गिरावट हो रही है। प्रदेश में वर्ष 2017 में जहां पराली जलाने के 8,784 मामले दर्ज किये गये थे,

बहुत ही कमी आई है। यही बजह है कि प्रदेश में साथ-साथ पराली की उपलब्धता बढ़ावा देकर मिट्टी की उर्वरता में सुधार किया गया। इससे किसानों की घटनाओं की घटनाएं की नियन्त्रित करने में कई जिलों ने अहम भूमिका निभाई है। इनमें से 151, कुशीगढ़र में 111 में दर्ज की गई है। इनमें से सरसे कम घटनाएं महाराजगढ़ में 468, झारी में 151, कुशीगढ़र में 118 और फतेहपुर में 111 में दर्ज की गई हैं। इन जिलों ने बैठक आयोग और जगरनीयों के अंतर्गत पराली को जलाने की समर्यादा जो लाभ समय से आय के नए स्रोत उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यही बजह है कि प्रदेश में साथ-साथ पराली की उपलब्धता बढ़ावा देकर मिट्टी की उर्वरता में सुधार किया गया। इससे किसानों की घटनाओं की घटनाएं की नियन्त्रित करने में कई जिलों ने अहम भूमिका निभाई है। इनमें से 151, कुशीगढ़र में 111 में दर्ज की गई है। इनमें से सरसे कम घटनाएं महाराजगढ़ में 468, झारी में 151, कुशीगढ़र में 118 और फतेहपुर में 111 में दर्ज की गई हैं। इन

















